नववर्ष की पूर्व संध्या पर दूध वितरण

जयपुर। मालवीय नगर वॉर्ड 131 के एक प्रमुख चौराहे पर नववर्ष के उपलक्ष में दूध वितरण का कार्यक्रम किया गया। पार्षद गोविन्द छीपा ने कहा कि दूध दही वाले हमारे भारत देश में मादक पदार्थों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर विधायक काली चरण सराफ, सुमन शर्मा, सन्नी कपूर, गंगा राम सैनी, गणेश सैनी, राम कृपाल, नीरजा सक्सेना सहित अनेक गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित रहे।

सहकारिता मंत्री गौतम दक ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

जयपुर। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम दक ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई की। मंत्री गौतम दक ने बताया कि भाजपा में कार्यकर्ता को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। कार्यकर्ताओं के कार्यों को संगठन के माध्यम से सत्ता के मंत्री प्राथमिकता दे रहे है, इससे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी मंशा के साथ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू की है, इसके परिणाम भी अब आना शुरू हो गए है। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई में आने वाले परिवादों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की सुनवाई सरकार में होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यकर्ताओं की समस्याएँ दूर होंगी और उनके क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान होगा तो संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा तो सरकार भी सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई की जा रही है, वहीं मंत्रियों के निवास पर जनसुनवाई पूर्व की भांति निरंतर सुचारू है। प्रदेश के आमजन कभी भी मंत्रियों के निवास पर जनसुनवाई में आ सकते है। प्रदेश कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा कार्यालय सचिव मुकेश पारीक भी उपस्थित रहे।

'राजस्थान में सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे घर, लहलहा रही फसलें'

प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35 हजार मेगावाट से अधिक हुई

जयपुर (कासं)। नववर्ष का सूरज प्रदेश के लिए नई उम्मीदों की किरणें लेकर आया है। विषम भौगोलिक हालात व मौसम के प्रचण्ड प्रकोप की मार झेलने वाला राजस्थान अब सूरज के विकास रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आमजन के घर सूर्यघर बन रहे हैं। सौर ऊर्जा से मिल रहे पानी से खेतों में सिंचाई हो रही है। बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में नम्बर वन राज्य के रूप में राजस्थान नए साल में प्रवेश कर रहा है।

ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब राजस्थान को कोयले की किल्लत के कारण बिजली संकट का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष में 320 दिन मिल रहे सूर्य के प्रकाश को प्रदेश का ऊर्जा परिदृश्य बदलने का जरिया बनाया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से नीतिगत निर्णय किए गए, निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया और भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया।

इससे परियोजनाएं समय पर पूरी होने लगी जिससे 2 साल में ही प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर दोगुनी हो चुकी है और राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

वर्तमान में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35 हजार 910 मेगावाट पहुंच चुकी है, जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27 प्रतिशत है। बीते दो वर्षों में राज्य की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18 हजार मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। भूमि पर लगी देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से 31 हजार मेगावाट का योगदान राजस्थान का है। राजस्थान इस प्रगति से देश के सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है।

विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि पीएम कुसुम में स्थापित ऊर्जा क्षमता दो साल में 122 मेगावाट से बढ़कर 2629 मेगावाट हो गई। कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत प्रदेश की गांव-ढाणियों में 2 हजार 629 मेगावाट क्षमता से अधिक की ग्रिड कनेक्टेड 1 हजार 201 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत 478 मेगावाट क्षमता के 368 प्लांट तथा कम्पोनेंट-सी में 2 हजार 151 मेगावाट क्षमता के 833 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इस तरह स्थापित ऊर्जा क्षमता में कम्पोनेंट-ए में राजस्थान प्रथम स्थान पर और कम्पोनेंट-सी में तीसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने का वादा किया था। आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। सौर ऊर्जा का इसमें बड़ा योगदान है। पीएम कुसुम योजना के सभी कम्पोनेंट्स से 2 लाख 83 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। बीते दो साल में पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी में 58 हजार 361 सोलर पम्पसैट की स्थापना की गई है। सस्ती सौर ऊर्जा मिलने से किसानों की डीजल पंपों पर निर्भरता कम हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर घर को ऊर्जादाता बनाने की पहल पर शुरू की गई पीएम सूर्यघर योजना में भी राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। आमजन रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाकर ना केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली से आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं। प्रदेश में 481 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 20 हजार 162 रूफटॉप सोलर संयंत्र पीएम सूर्यघर योजना में लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल 1948 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को 824 करोड़ की केन्द्रीय सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।

सौर ऊर्जा से घरेलू उपभोक्ताओं की बचत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की शुरूआत की है। अक्टूबर माह में पंजीकरण शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख 69 हजार से अधिक उपभोक्ता 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना से जुड़ने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 17 हजार रूपए की राज्य सब्सिडी हस्तांतरित की जाती है। राज्य सब्सिडी की यह राशि पीएम सूर्यघर योजना में देय अधिकतम 78 हजार रूपए की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

प्रदेश में पीक ऑवर्स में अब तक अधिकतम डिमांड 19 हजार 165 मेगावाट रही है, जो 2030 तक 25 हजार 48 मेगावाट होना अनुमानित है।

- **सौर ऊर्जा के कारण आमजन को महंगी बिजली से मिल रही राहत, घट रही कोयले पर निर्भरता**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के त्वरित और दूरदर्शी निर्णयों से राजस्थान की सोलर हब के रूप में बन रही वैश्विक पहचान**

आई.पी.एस. प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा बने एडीजी

9 आईपीएस आईजी रैंक पर प्रमोट हुए, 11 बने डी.आई.जी.

जयपुर (कासं)। भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के 2001 बैच के वरिष्ठ अधिकारी प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा को राज्य सरकार ने पदोन्नति देकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया है। उन्हें महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को आदेश जारी कर 40 आई.पी.एस. अधिकारियों को पदोन्नति दी है।

इसी प्रकार वर्ष 2008 बैच के 9 आई.पी.एस. अधिकारियों को उपमहानिरीक्षक से महानिरीक्षक वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया है। इस आदेश से लवली कटियार, डॉ. प्रीति चंद्रा, राहुल कोटोकी, डॉ. विकास पाठक, डॉ. राहुल जैन, ओमप्रकाश द्वितीय, राजेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद गोयल और कालूराम रावत अब पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.) होंगे।

इसी तरह वर्ष 2012 बैच के 11 आई.पी.एस. अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला से उपमहानिरीक्षक (डी.आई.जी.) वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। इनमें आईपीएस राशि डोगरा डूडी, ममता गुप्ता, पूजा अवाना, आदर्श सिद्धू, डॉ. किरन कैंग सिद्धू, जय यादव, अभिजीत सिंह, शांतनु कुमार सिंह, देवेन्द्र कुमार विश्नोई, विनीत कुमार बंसल, नारायण टोगस शामिल है।

- **राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 40 अफसरों को दिया पदोन्नत**

इसी प्रकार वर्ष 2013 बैच के 9 आई.पी.एस. अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। इनमें तेजस्वनी गौतम, चूनाराम जाट, मनीष त्रिपाठी, सुधीर जोशी, राज कुमार चौधरी, सुरेन्द्र सिंह, संजीव नैन, नरेन्द्र सिंह और योगेश गोयल शामिल है। इसी तरह वर्ष 2017 बैच के 3 आईपीएस को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला (लेवल-12) में पदोन्नत किया है। इनमें राजर्षि राज वर्मा, शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया और वंदिता राणा शामिल है। इसी तरह वर्ष 2022 बैच के 6 आईपीएस को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नित दी है। इनमें उषा यादव, विनय कुमार डी.एच, पंकज यादव, आदित्य काकड़े, विशाल जांगिड़ और शिवानी शामिल है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने की मुलाकात

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत ने मोती डूंगरी गणेशजी के दर्शन कर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। कुमावत ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया।

क्लेम राशि नहीं देने पर बीमा कंपनी पर हर्जाना

जयपुर (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी बीमा राशि अदा नहीं करने पर बीमा कंपनी इफको टोकियो पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने बीमा क्लेम के रूप में 8.32 लाख रुपए परिवाद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित परिवादी के पक्ष में अदा करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश कबूल चन्द सैनी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि वाहन के फोटोग्राफ से यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना में वाहन टोटल लॉस हो गया था। ऐसे में सर्वेयर की रिपोर्ट को ठीक नहीं माना जा सकता।

- **बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश**

परिवाद में अधिवक्ता गोपाल शास्त्री ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विपक्षी बीमा कंपनी से साल 2016 में अपना वाहन का बीमा कराया था। वहीं बीमा अवधि के दौरान जनवरी 2017 उसके वाहन की दुर्घटना हो गई। इस पर परिवादी ने क्षितग्रस्त वाहन को कंपनी के वर्कशॉप में भेजकर बीमा कंपनी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। परिवाद में कहा गया कि बीमा कंपनी ने सितंबर, 2017 में बीमा क्लेम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिवादी ने समय पर बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि घटना की जानकारी देरी से देने के आधार पर क्लेम के दावे को खारिज नहीं किया जाए। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने उसके क्लेम को खारिज कर दिया। ऐसे में उसे बीमा राशि और हर्जाना दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने को कहा है।

सेवा परिलाभ और वरिष्ठता वापस लेने के आदेश पर रोक

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही भर्ती में बाद में नियुक्त प्रबोधकों को दिए सेवा परिलाभ सहित अन्य नोशनल परिलाभों को वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और अलवर डीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण सिंह राजपूत व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रबोधक पद के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को साल 2009 में नियुक्ति मिली थी। वहीं याचिकाकर्ताओं को कई सालों बाद साल 2017 में नियुक्ति दी गई। वहीं साल 2018 में उन्हें अदालती आदेश की पालना में पूर्व में लगे अन्य प्रबोधकों के समान सेवा परिलाभ व अन्य नोशनल परिलाभ दिए गए। याचिका में कहा गया कि गत 3 नवंबर को शिक्षा विभाग ने साल 2018 में दिए आदेश को वापस ले लिया और इस अवधि में दिए गए वेतन को अधिक बताकर उसकी रिकवरी निकाल दी। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा गया कि एक भर्ती में अलग-अलग समय पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को एक समान वेतन परिलाभ और वरिष्ठता दी जाती है।

15 लाख की ड्रग्स के साथ विदेशी नागरिक सहित पांच गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार करते हुए पन्द्रह लाख रुपये की अवैध मादक पदार्थ जब्त कर एक विदेशी नागरिक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्मैक, एमडी ड्रग्स, कोकीन, नशीली गोलियां और एक कार बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने बगरू,शिवदासपुरा और कानोता थाना इलाके में संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली से जयपुर आ रहे विदेशी नागरिक ऑगस्टीन एग्बो (27) निवासी एनुगू (नाइजीरिया) हाल फरीदाबाद (हरियाणा),संगीता सांसी उर्फ मोगली(30) निवासी रामगंज जिला अजमेर, अब्दुल गफ्फार खान (30) निवासी माधोराजपुरा जयपुर, आरिफ मोहम्मद (26) निवासी माधोराजपुरा जयपुर ग्रामीण और विजय सोलंकी निवासी माधोराजपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 179.09 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक,12.26 ग्राम एमडी ड्रग्स (क्रिस्टल), 27.17 ग्राम कोकीन, 81 मिलीग्राम (2 टैबलेट) नशीली गोलियां सहित एक चौपहिया वाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि नाइजीरियन नागरिक के पास से वैध पासपोर्ट व वीजा नहीं मिला है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ऑपरेशंस) राहुल प्रकाश के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह के सुपरविजन में तीनों थाना क्षेत्रों में अलग-अलग की गई है।

- **स्मैक, एमडी ड्रग्स, कोकीन, नशीली गोलियां और कार बरामद**
- **जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बगरू, शिवदासपुरा और कानोता में कार्रवाई की**

पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और तकनीक-सक्षम बनाएंगे : राजीव शर्मा

जयपुर। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वर्ष 2026 के लिए राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जन-सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जनविश्वास को केंद्र में रखते हुए पुलिस तंत्र को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील एवं तकनीक-सक्षम बनाया जाएगा।

डी.जी.पी. राजीव शर्मा ने बताया कि अपराध संबंधी प्राथमिकताओं के अंतर्गत संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त एवं निर्णायक कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, जिसमें त्वरित कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

44 पुलिस निरीक्षकों को मिला आर.पी.एस. कैडर

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस के 44 पुलिस निरीक्षकों को नए साल पर तोहफा देते हुए उन्हें आरपीएस अधिकारी के रूप में पदोन्नित किया है। सरकार की विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिश के आधार पर गृह (ग्रुप-1) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें जयपुर ग्रामीण के चौमू थाने के थानाधिकारी प्रदीप शर्मा का भी नाम शामिल है। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा हाल ही में चौमूं में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी मामले को लेकर चर्चा में आए थे। उनको लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि प्रदीप शर्मा चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। प्रदीप शर्मा अब आरपीएस रैंक के अधिकारी बन गए हैं।

गृह (ग्रुप-1) विभाग के संयुक्त सचिव आनंदीलाल वैष्णव की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार पुलिस निरीक्षक देवेंद्र प्रताप वर्मा, मदनलाल, राजेंद्र बाफना, अचलदान रत्नू, पुरुषोत्तम महरिया, बनवारी लाल मीणा, बाबूलाल मीणा, रामनिवास मीणा, अजयकांत रतूडी और रविंद्र कुमार को आरपीएस अधिकारी के पद पर पदोन्नित मिली है। इसी प्रकार पुलिस निरीक्षक मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र पेवा, बाबूलाल चौधरी, सरोज धायल, शिखा विश्नोई, बुद्धाराम, छत्तर सिंह, देरावर सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, राजेश यादव, राजकुमार टेलर, निशा भटनागर, घनश्याम शर्मा, लक्ष्मीनारायण, दिनेश कुमार, निरंजन प्रताप सिंह, श्याम सिंह रत्नू, महावीर सिंह यादव, वीरेंद्र कुमार, रणजीत सिंह, अशोक चौधरी, रविंद्र प्रताप, मांगीलाल विश्नोई, नरेंद्र कुमार , प्रदीप कुमार शर्मा, राजीव भादू, नरपत सिंह, लक्ष्मण राम विश्नोई, आनंद कुमार, दुर्गाप्रसाद दाधीच, नवनीत बिहारी व्यास, परवेज आलम सैयद, अनिल कुमार मूंड और लाखन सिंह खटाना को आरपीएस के पद पर पदोन्नित दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पदोन्नत सभी इंस्पेक्टर अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक 2 दिसंबर 2025 को हुई थी और इस समिति की अनुशंसा पर गृह विभाग ने आदेश जारी कर इन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया।

अवैध खनन पर 14 एफआईआर, एक गिरफ्तारी और 28 लाख रु. का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई

जयपुर। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के 20 जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाये जा रहे संयुक्त अभियान में पलियाना में अलवर सिक्सलेन निर्माण कार्य कर रही कंपनी द्वारा अवैध खनिज मिट्टी खनन पर जयपुर अधीक्षण अभियंता एनएस शक्तावत की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 लाख रुपए से अधिक के जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। टोंक में भी रेल्वे ट्रेक के लिए काम कर रही निजी कंपनी द्वारा अवैध खनिज मिट्टी खनन कार्रवाई पर एक एक्सक्वेटर 4 डंपर जब्त किये हैं। नागौर के एमई श्री जय गोदारा द्वारा रियाबड़ी में दो ट्रेक्टर बजरी के व खींवसर में दो डंपर चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए जब्त करते हुए करीब 3.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जोधपुर के बड़ली क्षेत्र में खनिज सेंड स्टोन के क्वारी लाइसेंस के 40 हैक्टेयर क्षेत्र में अधीक्षण खनि अभियंता डॉ. देवेन्द्र गौड की टीम द्वारा ड्रोन सर्वे करवाया गया है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संबंधित जिलों में संयुक्त जांच दल द्वारा कार्रवाई जारी है। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के जिलों में 29 दिसंबर से अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जिला कलक्टरों द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों से जारी अभियान के दौरान दो दिन में ही उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक उपकरणों और वाहनों की जब्ती की जा चुकी है। अभियान के दौरान दो दिन में ही 155 से अधिक कार्रवाई कर 12 एक्सक्वेटर/जेसीबी/क्रेन व 137 डंपर-ट्रेक्टर आदि जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द किये जा चुके हैं।

आर.पी.एस. अधिकारी एक करोड़ रुपए वसूली के आरोप में गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। महेश नगर थाना पुलिस ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.पी.एस.) अधिकारी रितेश पटेल को एक करोड़ रुपये की वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरपीएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को धमकाकर एक करोड़ रु. की मांग की और एसओजी के नाम से फर्जी एफआईआर तैयार कर भेजी। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक करोड़ रुपए की मांग में से 25 लाख रुपये नकद और 25 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि एसओजी की फर्जी एफआईआर तैयार कर शिकायतकर्ता को भेजने और रुपये मांगने का आरोप है।

महेश नगर थाना पुलिस ने एपीओ (अटैच्ड पुलिस ऑफिसर) चल रहे आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को उनके केसर चौराहा स्थित घर से गिरफ्तार किया।

पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरपीएस रितेश पटेल ने धमकी देकर एक करोड़ रुपये मांगे और एसओजी के नाम से फर्जी एफआईआर बनाकर भेजी। पुलिस अब आरोपित आरपीएस से गहन पूछताछ कर रही है।

आरोपित रितेश पटेल 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी है। वह बजरी लेनदेन के एक मामले में पहले से एपीओ चल रहे है।

आर.पी.एस. रितेश पटेल

- **आरपीएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को धमकाकर एक करोड़ रु. की मांग की और एसओजी के नाम से फर्जी एफआईआर तैयार कर भेजी।**
- **शिकायतकर्ता का कहना है कि एक करोड़ रुपए की मांग में से 25 लाख रुपये नकद और 25 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए।**

बजरी के ट्रैक्टर छोड़ने का बनाया था दबाव

गंगापुर सीआई फूलचंद ने साल 2024 में आशाहोली गांव के पास अवैध बजरी भरकर ले जा रहे दो ट्रैक्टर पकड़े थे। ट्रैक्टरों को थाने लाकर खड़ा करवाया था। सीआई ने इस कार्रवाई से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया था। दोनों ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। इनके चेसिस नंबर पर भी जून 2024 की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी। माना जा रहा था कि ट्रैक्टर मालिक ने खरीदने के बाद आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था।

तब तत्कालीन डीएसपी रितेश पटेल थाने पहुंचे थे। डीएसपी ने दोनों ट्रैक्टरों को छुड़वाने की कोशिश की थी, परंतु सीआई ने उनकी बात नहीं मानी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। सोशल मीडिया पर भी मामला काफी छाया रहा था। इसके बाद रितेश पटेल को एपीओ कर दिया था।

कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच चल रही है कि आरोपित आरपीएस अधिकारी ने कितने रुपये लिए गए और कैसे लिए गए। इसकी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा जांच पूरी होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित आरपीएस को पुलिस रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ होगी।

सड़क हादसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत

जयपुर। कोटखावदा इलाके में स्थित जयपुर-टोंक हाईवे (एनएच-52) कोटखावदा पुलिया पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल जा रहे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत हो गई। दुर्घटना थाना इंचार्ज रामरतन चौधरी ने बताया कि मृतक की पहचान चाकसू निवासी 45 वर्षीय हेमराज गोस्वामी के रूप में हुई है। जो ठीकरिया मीणान गांव स्थित सरकारी स्कूल में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के पद पर कार्यरत था और बुधवार सुबह बाइक से स्कूल जा रहे थे। पुलिस के अनुसार हाईवे पर लघुशंका के लिए रुकने के बाद हेमराज गोस्वामी जैसे ही दोबारा बाइक पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। तभी पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायल को चाकसू उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के साले राजेश गोस्वामी ने बताया कि हेमराज गोस्वामी के दो बेटे और एक बेटी हैं।

जयपुर में आर्मी-डे परेड पर 6 वर्ग कि.मी. इलाका होगा सील

सुरक्षा के लिए कमांडो-आरएसी-पैरामिलिट्री होगी तैनात

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में स्थित महल रोड पर 15 जनवरी 2026 को होने वाली आर्मी-डे परेड को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल से अक्षय पात्र तक फैले करीब 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने की तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस इलाके में रहने और काम करने वाले पचपन हजार से अधिक लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है।

इसके लिए 300 पुलिसकर्मियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। सुरक्षा को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है। बाहरी घेरा पुलिस और आरएसी संभालेगी, मध्य घेरा पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे रहेगा, जबकि सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान सीधे भारतीय सेना के हाथों में होगी।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से आर्मी डे परेड की नियमित रिहर्सल शुरू होगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बाहरी सुरक्षा के लिए आरएसी की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। मध्य सुरक्षा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स संभालेगी, जबकि अंतिम और सबसे संवेदनशील घेरे की जिम्मेदारी सेना के पास रहेगी। एडिशनल कमिश्नर (कानून व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि कॉलोनी विकास समितियों, मॉल प्रबंधन और व्यापार संघों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए गए हैं। रिहर्सल के दौरान क्षेत्र में पतंग उडाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और पूरा इलाका नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। नए किराएदारों, घरेलू सहायकों और दुकानों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इस कार्य की मॉनिटरिंग एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल द्वारा किया जा रहा है। वहीं एसीपी सांगानेर हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीमें रोजाना फ्लैग मार्च निकाल कर माइक के जरिए लोगों को सुरक्षा नियमों के पालन और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। परेड रूट के आसपास स्थित सभी ऊंची इमारतों को विशेष निगरानी में रखा गया है। इन इमारतों पर लाल झंडे लगाकर मार्किंग की जाएगी। साथ ही छतों पर सेना के कमांडो तैनात रहेंगे। जो दूरबीन और स्नाइपर के माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे।

- **बाहरी घेरा पुलिस और आरएसी संभालेगी, मध्य में पैरामिलिट्री, अंतिम सुरक्षा सेना के हाथ में**
- **ऊंची इमारतों पर कमांडो, नो-ड्रोन जोन, पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध**